

Golden Jubilee Year 2017-18



VINDHYA BHARTI **(A Research Journal)**

UGC Recognized

विन्ध्य भारती **(शोधपत्रिका)**



Awadhesh Pratap Singh University
Rewa - 486003 M.P., India

सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रभावोत्पादकता का अध्ययन

डॉ. प्रीति कुशवाहा
अतिथि विद्वान (वाणिज्य)

शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना (म.प्र.)

सारांश :-

स्वतन्त्रता पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन हुए जिनके कारण आर्थिक जगत में उथल-पुथल की स्थिति देखी गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत को कमजोर औद्योगिक आधार पर अर्द्धविकसित व गतिविहीन अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। सन् 1947 में देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना एवं विकास के लिए 1951 में नियोजन को अपनाये जाने के बाद भारत आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त हो पाया है। इसी तारतम्यत में 1991 की औद्योगिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की तथा सुदारीकरण ने इसमें नए आयामों को जोड़कर आर्थिक क्रियाकलापों को नई दिशा दी। वर्ष 1956 में नवीन मध्यप्रदेश का गठन किया गया। जिसमें महाकौशल मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, जैसे क्षेत्रों को मिलाकर एक नए प्रदेश की स्थापना की गयी। भारत में मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ की श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश के समस्त जिलों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए स्वरोजगार मूलक योजनाओं का पूरी दृढ़ता से क्रियान्वयन किया है।

भारत का विकास भारत के ग्रामीण विकास पर निर्भर है। बगैर ग्रामीण विकास के विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में ग्रामीण विकास गांवों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर ही संभव है ग्रामीण जनो के लिए आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएँ उसी स्थिति में हो सकती है, जब ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जनता की अधिकाधिक सहभागिता हो, इस हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज-संस्थाएँ, सरकारी विभाग और जन प्रतिनिधि निरंतर प्रयत्नशील होने चाहिये।

प्रस्तावना :-

भारत ग्राम प्रधान देश है। देश की लगभग 72 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, यहां के लोगों के जीविका का आधार कृषि हैं। स्वतंत्र भारत की आजादी के पश्चात् महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के अनुभवों के आधार पर समुन्नत, सुदृढ़ और सशक्त भारत की कल्पना की थी। अपने अनुभवों एवं चिंतन पर आधारित वे भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहते थे जिसकी शासन व्यवस्था एवं नीति